ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **8 April, 2020**

Shri Ghulam Nabi Azad, Leader of Opposition (Rajya Sabha) addressed the media today.

श्री गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री जी ने राज्य सभा और लोक सभा के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात हुई, तकरीबन 15-16 राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उसमें हिस्सा लिया। शुरुआत हमसे हुई, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर और उसके किसानों, लोगों और देश पर हुए असर को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को अनेक पत्र लिखे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील ये होगी कि उन पर अमल करें।

मैंने प्रधानमंत्री जी का ये भी धन्यवाद किया कि एक इस तरह के पत्र में कुछ दिन पहले श्रीमती सोनिया गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लैटर में लिखा था कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लाखों वर्कर हैं, उनका एक वेलफेयर फंड होता है, जिसमें तकरीबन 30 हजार करोड़ रुपए होते हैं, वो बजाए फंड कहीं जमा रखने के, इसको आज उन वर्कर्स के बीच में बांटना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने, जो ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने बताया कि इस वेलफेयर फंड को बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच में बांटा जाएगा, तो उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। तो सोनिया गांधी जी के बहुत सारी मांगों में से एक मांग ये भी थी।

कांग्रेस की तरफ से, मैंने अपनी पार्टी की तरफ सेक्टर वाइज 5-6 मांग रखी। हेल्थ वर्कर के बारे में हमने बताया कि जो भी डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करते हैं, एम्पलोई हैं, सैनिटाइजेशन वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, इनको जो दिक्कत आ रही है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की, सरकार को सबसे पहले इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वो खुद सुरक्षित हैं, तभी पैशेंट सुरक्षित भी होंगे और देश भी सुरक्षित होगा। तो इसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान, वेंटिलेटर से लेकर पीपीई की तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए।

दूसरी बात बताई, फ्रंट लाइन वर्कर का इंशोरेंस किया जाना सबसे जरुरी है। इसी तरह से जो वायरस है, जो बीमारी है, इसके बारे में हमने बताया कि अगर इसको जड़ से खत्म करना है तो सख्त- कड़े कदम लेने

की जरुरत है और इस बीमारी को ढूंढने के लिए, पैशेंट को ढूंढने के लिए, उसके टेस्ट करने के लिए, उनको आइसोलेट करने के लिए, इलाज करने के लिए हमारा सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

हमने ये भी बताया कि अब समय आ गया है कि टारगेटेड़ और सेक्टर वाइज लेन बननी चाहिए। टारगेटेड मतलब जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग पाए गए हैं एरिया में, वहाँ टारगेट किया जाए, सेक्टर में बांट दिया जाए और वहाँ सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो फिजिकल डिस्टेंस है, जिसको हम आम तौर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत जरुरी है, उस पर जितना बल दिया जा रहा है, वो काफी नहीं है, इसमें और प्रयास होना चाहिए इस पर बल देने के लिए। जो टेस्टिंग है, वो फ्री होनी चाहिए, जितनी आज टेस्टिंग है, तकरीबन हमारी जो कपैसिटी है, वो बहुत ही कम है। इतने बड़े देश के लिए मौजूदा टेस्टिंग फैसिलिटीस ना होने के बराबर है, जितने लोग एक दिन में टेस्ट होते हैं, उससे कई गुना होने चाहिएं, इसलिए जो बीएसएल 2, बीएसएल 3 लैब की फैसिलिटी है, उनको तुरंत दोगुना और तीगुना कर देना चाहिए। ये बात हमने वायरस और हेल्थ वर्कर के बारे में कही।

दूसरा प्वाइंट हमने लिया, लेबर के बारे में। करोडों लेबर हैं, 39 हजार करोड़ से 45 करोड़ के करीब हमारी आबादी में हमारे सिर्फ मजदूर ही हैं और हर तरीके के लेबर हैं, कंस्ट्रक्शन के लेबर, सड़कों पर काम करने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले, अस्पताल, स्कूल, इंडस्ट्री, पॉवर प्रोजेक्ट बनाने वाले, जितने भी हमारे जो वर्कर्स हैं, वो आज सबसे ज्यादा परेशान हैं और इतने ज्यादा वर्कर्स अगर हमारे देश में भूखे रहेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज इस देश में जो भी प्रगति हुई है आजादी के बाद, तो सिर्फ इन वर्कर्स की वजह से हुई है। अगर हमारा वर्कर, जिनके साथ, जिनकी वजह से आज हमारा देश इतना प्रगतिशील बना है, तो उनके साथ जब सब खड़े नहीं होंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, इसलिए उनके लिए जितने भी इंतजाम, जितने भी कदम हों, वो उठाने चाहिएं, उनको मुफ्त राशन देने की इस वक्त आवश्यकता है और ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, तहसीलदार की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं हैं या जिनके पास और कोई सुविधा नहीं है, तो तहसील लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर कमेटियां बननी चाहिएं, जिसको राशन नहीं मिल पा रहा है तो उसको मिलना चाहिए। आमतौर पर सरकार कई सुविधाएं प्राप्त करती है, लेकिन वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचती है, तो उसका बंदोबस्त भी जरुरी करना होगा।

तीसरी चीज हमने एग्रीकल्चर और किसानों के बारे में बताई।आज ऐसा मौसम चल रहा है, आज रबी का मौसम है। सरसों की कटाई हो चुकी है, गेहूं की कटाई हो रही है और ऐसे में, लॉकडाउन के हालात में, एमएसपी बढ़ाने की जरुरत है, प्रोक्योरमेंट जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया फूड मिनिस्ट्री की होती है, उसको बढ़ाने की जरुरत होती है। मंडियों में प्रोक्योरमेंट की जरुरत है और जितने भी फार्मर्स हैं, उनके जो लोन हैं, उनकी अदायगी तकरीबन 6 महीने के लिए बिल्कुल टाल देनी चाहिए और फार्मर्स की जो क्रेडिट कार्ड की लीमिट है, वो बढ़ा देनी चाहिए। इसी तरह से हमारे पास करोडों मजदूर हैं, जो मनरेगा में काम करते हैं। एक तरफ से आप कहते हैं कि मनरेगा वालों के हम पैसे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे लेकिन काम किए बगैर तो आप उनको पैसे देंगे नहीं, तो उसका सबसे बेस्ट इलाज है कि आज जहाँ रबी की फसल काटी जा रही है और कुछ एक-आध महीने के बाद फिर राइस की फसल उगाने का काम शुरु हो जाएगा, तो

क्यों ना हम इन मनरेगा वर्कर्स को हार्वेस्टिंग का काम दें दें, तो उनको मजदूरी भी मिलेगी और किसान की जो रबी की फसल उगाई है, उसकी भी मुफ्त में कटाई हो जाएगी। तो मनरेगा वर्कर्स को भी मजदूरी मिलेगी और किसान की फसल की कटाई भी मुफ्त में होगी, तो दोनों को फायदा होगा।

इसी से जुड़कर हमने फार्मर्स और एग्रीकल्चर से संबंधित जो सुविधाएं हैं, उनकी भी बात की, कि जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर जीएसटी लगा है, पहले जीएसटी नहीं होता था, उन पर टैक्स नहीं होता था, लेकिन एक-दो साल पहले से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर जीएसटी लगा है, तो मौका आ गया है कि उन पर जीएसटी खत्म किया जाए। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैं - मशीनरी हैं, ट्रैक्टर्स हैं, दूसरी चीजें हैं, उन पर पहले टैक्स नहीं होता था, लेकिन उन पर भी जीएसटी लगा है, तो ये मौका आ गया है कि अगर किसानों की हमें सहायता करनी है, मदद करनी है तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, ट्रैक्टर और बाकी इक्विपमेंट, हम उन पर से जीएसटी हटा दें।

इसके साथ ही हमने बताया कि सरकार की एक टास्क फोर्स है, केन्द्रीय मिनिस्टरों को लेकर, लेकिन ये काफी नहीं हैं, इसमें कॉर्डिनेशन की जरुरत है, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर गवर्मेंट के बीच में, इसलिए कुछ मुख्यमंत्री भी उस टास्क फोर्स का हिस्सा होने चाहिएं। कुछ सेंटर के मिनिस्टर्स और कुछ चीफ मिनिस्टर्स और उन चीफ मिनिस्टर्स का चयन उस आधार पर किया जा सकता है कि जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का असर है, उन चीफ मिनिस्टरों को उस टास्क फोर्स में लिया जा सकता है। सेंटर और स्टेट की पॉलिसी बनेगी तो वो एक समाधान निकाल सकते हैं कि क्या लोगों के आने वाले वक्त में, लोगों को, मजदूरों को, किसानों को और आम जनता को किस तरह की सुविधाओं की जरुरत है, क्योंकि केन्द्रीय मंत्री दिल्ली में रहते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर स्टेट के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, उनको जानकारी ज्यादा होती है।

इसी तरह से हमने रिक्वेस्ट की कि जो सांसद और विधायक हैं, उनको भी इस काम में जोड़ना चाहिए, उससे सरकार की मदद हो सकती है और लोगों की मदद हो सकती है। आज भी राजनीतिक पार्टी के चाहे वो पदाधिकारी हों, जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी के एमपी हों या चुने हुए दूसरे प्रतिनिधि हों, आज भी वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑफिशियली उनको इस काम में लगाया जाए, तो वो बहुत अच्छा होगा।

इसी तरह से हमने एक मल्टी पॉलिटिक्ल पार्टी के लीडर्स की एक वर्किंग ग्रूप की बात की, ताकि उनका मोराल भी उससे ऊंचा हो जाए और सरकार को एक गैर सरकारी तरीके से भी पॉलिटिक्ल पार्टी के द्वारा जानकारी मिलना शुरु हो जाए।

इसी से जुड़ी हमने एक बात और बताई कि स्पेशल फाईनेंशियल पैकेज उन राज्यों को देना चाहिए, जहाँ सबसे ज्यादा इस बीमारी का असर है, उनके रिसोर्सिस कम हैं। मैंने पुडुचेर्री की मिसाल दी, पुडुचेर्री जैसे छोटी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं, इस तरह के कई स्टेट हो सकती हैं, यूनियन टेरिटरी हो सकती हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार को बहुत सारा पैसा देना है, ड्यू है स्टेट के प्रति, लेकिन उनको मिलता नहीं है, तो ये

समय है ऐसी स्टेटों के, जिनके अपने साधन नहीं हैं और ड्यू है केन्द्र सरकार की तरफ, उन सरकारों का पैसा, वो तुरंत दे देना चाहिए।

आखिर में हमने ये भी गुजारिश की कि कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस लीडरशिप ने जितने भी सुझाव दिए हैं, उनको पूरा करना चाहिए। एजूकेशन के बारे में हमने बताया कि एजूकेशन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो आज कल एग्जाम होते थे, वो तो कई महीनों से वैसे ही नहीं चल रहे थे, जैसे जम्मू-कश्मीर में तो 7-8 महीनों से ही एजूकेशन का सिस्टम खत्म हो चुका था, लेकिन अभी एक-आध महीने से पूरे देश में जो एनुअल एंट्रेंस एग्जेमिनेशन का सिलसिला था, वो धूमिल हो गया है, तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह से इंडस्ट्री के बारे में हमने कहा कि, सप्लाई चैन तो बहुत जरुरी है, लेकिन उसके लिए प्रोडक्शन भी उतना ही जरुरी है, जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो सप्लाई चैन आप कैसे मैंटेन करेंगे। इतने बड़े देश में जहाँ लॉकडाउन हो, अगर वहाँ हमारी सप्लाई चैन रुक जाए और प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई चैन रुक जाए, तो फिर लोग शायद बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन बाकी जो एंशेशल सर्विसेज हैं, उनके ना होने की वजह से वो मुसीबत में आ सकते हैं, खास तौर से इसमें जो फार्मासुटिकल यूनिट हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, ऐसी इंडस्ट्री को भी जारी रखना चाहिए, चालू रखना चाहिए।

All the Congress ruled states Chief Minister's have demanded extension of the lockdown and what is Congress Party's opinion on extension of lockdown, Shri Azad said- आज की मीटिंग में अधिकतर मैं ये कहूँगा कि 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने पॉलीटिकल पार्टीज ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात की लेकिन आखिर में सबने ये प्रधानमंत्री जी पर छोड़ दिया है कि जैसा वो उचित समझें, वो करें। तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में अपने भाषण में बताया कि मुझको भी चारों तरफ से ऐसी सूचना आ रही है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन मैं अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लूँगा। मैं फिर मुख्यमंत्रियों से बात करुँगा, दूसरे लोगों से बात करुँगा और जो भी देश के लिए उचित होगा, वो करुँगा।

एक अन्य प्रश्न पर कि कई राज्य हैं कांग्रेस शासित को मिलाकर, जो कि जीएसटी का जो बकाया है,उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, श्री आजाद ने कहा कि मैंने बताया कि बहुत सारे स्टेट्स ने इस मुद्दे को उठाया। मैंने तो कहा कि जो छोटी स्टेट्स हैं, उनको तो तुरंत देना चाहिए। जब मैं बकाया की बात करता था, केन्द्र सरकार की ओर उसमें जीएसटी और दूसरी चीजों का ही बकाया था, तो इसका बहुत सारे स्टेट ने उल्लेख किया, बड़ी स्टेटों ने भी, छोटे स्टेटों ने भी कि केन्द्र सरकार को जो पैसा देना है जीएसटी का और दूसरी कई हैड्स में और मनरेगा के हैड्स में भी तो उनको पैसा देना चाहिए, बल्कि बहुत सारे लीडरों ने ये भी कहा कि आपने एमपीलेड में दो साल का पैसा लिया है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जिस-जिस स्टेट के एमपीज हैं, उन्ही स्टेट्स को वो पैसा दिया जाना चाहिए।

लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री आजाद ने कहा कि पीएम ने उस समय बता दिया कि उनको भी सुझाव इधर उधर से आते हैं, लेकिन वो अभी कोई निर्णय नहीं लेंगे वो फिर दोबारा मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, अपने सहयोगियों से बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे समय के साथ जैसे भी जरुरत होगी, वैसा किया जाएगा।

On another question we are given to understand that Home Secretary and other secretaries gave a detailed presentation, what was about that, Shri Azad said- प्रिजेंटेशन बहुत छोटी दिख रही थी, तो हम उस वक्त देख नहीं पाए। लेकिन बहुत सारी थी, एक हैल्थ सेक्रेटरी ने, होम सेक्रेटरी ने, रुरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी की। रुरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी ने बहुत सारी सुविधाओं के बारे में बताया, कोविड के बारे में, लेकिन फोन्ट इतना छोटा था कि हम उस वक्त पढ़ नहीं पाए लेकिन उसके हिसाब से कुछ सुविधाएं, जो उन्होंने बताई हैं हालांकि वो सुविधाएं इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन पहले इंस्टॉलमेंट के जो रुपए उन्होंने वुमैन के लिए, ओल्ड ऐज पेंशन के बारे में तीन-तीन या छः-छः महीने के लिए इस तरह की चीजें होंगी। मुझे लगता है कि सरकार उसको रिलीज करे, जब उन्होंने दिखाया है तो जाहिर है कि वो रिलीज भी करेंगे।

एक अन्य प्रश्न पर कि कल सीएमआईई का डेटा रिलीज हुआ, जिसमें ये दिखाया गया कि आज अनएम्पलॉयमेंट और जॉब लॉसेस मैक्सिमम है, क्या आज उसके ऊपर कुछ चर्चा हुई, श्री आजाद ने कहा कि नहीं, उस पर नहीं हुई। क्योंकि स्वभाविक है कि उस पर पार्लियामेंट में इतनी बार चर्चा हुई है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही है, कई बार राज्यसभा, लोकसभा में चर्चा हुई है, जो अब भी देख रहे हैं और जाहिर है कि इस लॉकडाउन में तो अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ेगी, तो इसलिए कोई नया मुद्दा नहीं था, वो पुराना मुद्दा था। ये लॉकडाउन के बगैर भी इस सरकार के 6 साल के शासन में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है।

एक प्रश्न पर कि क्या इस बात पर कोई चर्चा हुई है कि कंप्लीट लॉकडाउन की जगह जिन राज्यो में जिन जगहों पर परेशानी हॉट स्पॉट पर है, उनको सील किया जाएगा, बाकी इलाकों को नॉर्मल रखा जाएगा, श्री आजाद ने कहा कि एक दो लीडरों ने वो सुझाव भी दिया कहा कि इसको भी कंसीडर करना चाहिए या पूरे देश में या पूरे स्टेट में ही करना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा ये महामारी है, वहीं करना चाहिए, कुछ लोगों ने ये सलाह दी है। पीएम साहब ने उस पर कोई पॉइंटवाइज नहीं बताया, उन्होंने 6-7 मिनट में अपनी बात खत्म की, उनका कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ, सब पॉलीटिकल पार्टीज का, एक दो शब्द मैंने उनके लिख लिए हैं मैं वही कहूँगा, कि आपके साथ इस वार्ता से हमारा विश्वास बढ़ गया है, आपका सहयोग मिल रहा है, मैंने सब सुझाव नोट किए हैं और मैं उन सुझावों पर पूरे तरीके से अमल करने की कोशिश करूँगा। मुझे खुशी है कि संकट के समय हम तमाम राजनीतिक दल अपनी राजनीति को भूलकर देश के उत्थान के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं और मुझे पुरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरह सब लोग इस महामारी का मुकाबला करेंगे। इस तरह से उन्होंने एक जनरल नेचर की बात की है।

On another question that you have been Union Health Minister as well, so, you would know this situation much clear. The problem with India is we are not testing as per the population level, we are testing much less that is one of the reason why experts are saying that the numbers shown to us, the figures given to us are much-much less, so one of the reason is Government has allowed private sectors to test, but, the cost is very high, Rs. 4,500, which a common man cannot afford, what is the Congress' opinion, Shri Azad said- as a matter of fact, this was my first point, I raised. There are agriculture, labour, extra issues that was my number two and number three, but, my first point, which I raised, was this virus stroke, health workers. I started with this, but, what is the most important is the Doctors, nurses, hospital administration, employees, sanitization workers, frontline workers are have to be protected and we have to provide them the Personal Protection Equipments, we have to provide them masks, we have the shortage of ventilators and the testing facilities are totally inadequate and which is why I said that we should immediately double or triple the numbers of BSL-2 and BSL-3 laboratories. I also mentioned that it doesn't cost more than two crore Rupees capital cost per unit. So, if you set up 200 more laboratories that means just 400 crores which is not much and I said where there is the testing is totally inadequate for population or 1.3 billion and I also said that the testing has to be totally free.

एक अन्य प्रश्न पर कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी, श्री आजाद ने कहा कि हमारे समर्थन करने का सवाल नहीं है इसमें। ये सरकार को देखना है, जो उन्होंने खुद बताया है कि मैं राज्य सरकारों से भी बात कर रहा हूँ और बात करूँगा। अगर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें उनके ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए वो जो मिलकर निर्णय लेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश से अलग नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री अलग-अलग पॉलीटिकल पार्टीज के हैं। अलग-अलग रीजन्स के हैं। वो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें मिलकर जो देश के हित में होगा, कांग्रेस पार्टी भी उसके हित में है। हमारा मकसद है कि ये बीमारी खत्म हो जाए। हमारी लड़ाई बीमारी के साथ है, कोरोना वायरस के साथ है। हमारी इस वक्त कोई आपसी सरकार और विपक्ष की कोई लड़ाई नहीं है इस मुद्दे को लेकर।

Sd/-
(Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC